

COVID-19 महामारी के दौरान MSMEs के लिए सरकारी सहायता योजनाएँ: एक आर्थिक विश्लेषण

डॉ. शबनम भारती

(पीएच.डी., अर्थशास्त्र विभाग, टी.एम. भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर)

सारांश

COVID-19 महामारी ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को गंभीर रूप से प्रभावित किया, जिसमें सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSMEs) क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में से एक था। भारत में MSMEs अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाते हैं क्योंकि यह क्षेत्र रोजगार सृजन, निर्यात वृद्धि तथा औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है। प्रस्तुत शोध-पत्र में COVID-19 के दौरान MSMEs के लिए लागू सरकारी सहायता योजनाओं का आर्थिक विश्लेषण किया गया है। अध्ययन द्वितीयक आँकड़ों, सरकारी रिपोर्टों, RBI, IMF तथा विभिन्न शोध-पत्रों पर आधारित है। महामारी के दौरान लॉकडाउन, आपूर्ति श्रृंखला में बाधा, मांग में गिरावट तथा श्रमिक पलायन के कारण लाखों MSMEs आर्थिक संकट से गुजरने लगे। इस परिस्थिति में भारत सरकार एवं भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विभिन्न राहत एवं सहायता योजनाएँ लागू की गईं, जिनमें आपातकालीन ऋण गारंटी योजना (ECLGS), अधीनस्थ ऋण योजना, आत्मनिर्भर भारत पैकेज, मुद्रा योजना तथा MSME पुनरुद्धार योजनाएँ प्रमुख थीं। अध्ययन में यह पाया गया कि सरकारी योजनाओं ने MSMEs को वित्तीय राहत प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, किंतु योजनाओं की पहुँच, जागरूकता की कमी तथा प्रक्रियात्मक जटिलताओं जैसी समस्याएँ भी सामने आईं।

मुख्य शब्द: COVID-19, MSMEs, सरकारी सहायता योजनाएँ, आत्मनिर्भर भारत, आर्थिक पुनर्बहाली, ECLGS।

1. प्रस्तावना

भारत की अर्थव्यवस्था में MSMEs का विशेष महत्व है। यह क्षेत्र लगभग 30% GDP, 45% निर्यात तथा करोड़ों लोगों को रोजगार प्रदान करता है। महामारी से पहले भी MSMEs को वित्तीय संसाधनों की कमी, तकनीकी पिछड़ेपन तथा बाज़ार प्रतिस्पर्धा जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था। COVID-19 महामारी के दौरान लगाए गए लॉकडाउन ने इस क्षेत्र को गंभीर रूप से प्रभावित किया। उत्पादन बंद हो गया, श्रमिकों का पलायन हुआ तथा मांग में भारी गिरावट आई। RBI ने भी ऋण मोरेटोरियम, ब्याज दरों में कमी तथा MSMEs के लिए विशेष पुनर्गठन योजनाएँ लागू कीं। इन नीतियों का उद्देश्य MSMEs को तरलता उपलब्ध कराना तथा रोजगार एवं उत्पादन को बनाए रखना था।

भारत सरकार ने MSMEs को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से “आत्मनिर्भर भारत अभियान” के अंतर्गत कई योजनाएँ प्रारंभ कीं। इनमें ₹3 लाख करोड़ की आपातकालीन ऋण गारंटी योजना (ECLGS), ₹20,000 करोड़ की अधीनस्थ ऋण योजना तथा ₹50,000 करोड़ के फंड ऑफ फंड्स जैसी योजनाएँ शामिल थीं।

2. साहित्य समीक्षा

Economics के विभिन्न अध्ययनों में COVID-19 के दौरान MSMEs की चुनौतियों एवं सरकारी नीतियों की प्रभावशीलता का विश्लेषण किया गया है।

Behera एवं Mishra (2021) ने MSMEs की समस्याओं एवं सरकारी नीतियों के प्रभाव का विश्लेषण करते हुए कहा कि सरकारी प्रोत्साहन योजनाओं ने सीमित स्तर पर राहत प्रदान की, किंतु छोटे उद्यमों तक योजनाओं की पहुँच कम रही।

Subhash Sambhaji Agale (2021) ने पाया कि लगभग 45% MSMEs को महामारी के दौरान गंभीर राजस्व हानि हुई। अध्ययन में डिजिटल परिवर्तन एवं वित्तीय सहायता को पुनर्बहाली का प्रमुख कारक माना गया।

Akhilesh K. Sharma (2022) ने अपने अध्ययन में बताया कि महामारी के दौरान MSMEs को सबसे बड़ी समस्या कार्यशील पूंजी एवं ऋण उपलब्धता की रही। उन्होंने ECLGS योजना को MSMEs के पुनरुद्धार में महत्वपूर्ण बताया।

Silu Muduli (2022) के अनुसार ECLGS योजना के कारण MSME ऋण वृद्धि में सुधार हुआ तथा लगभग 88% ऋण खाते मानक परिसंपत्ति बने रहे।

इन अध्ययनों से स्पष्ट होता है कि सरकारी योजनाएँ उपयोगी थीं, लेकिन इनके कार्यान्वयन में कई व्यावहारिक कठिनाइयाँ भी थीं।

3. अध्ययन के उद्देश्य

1. COVID-19 महामारी के दौरान MSMEs की आर्थिक समस्याओं का अध्ययन करना।
2. MSMEs के लिए लागू सरकारी सहायता योजनाओं का विश्लेषण करना।
3. योजनाओं के कार्यान्वयन में आने वाली समस्याओं का अध्ययन करना।
4. MSMEs के भविष्य के विकास हेतु सुझाव प्रस्तुत करना।
5. योजनाओं के आर्थिक प्रभाव एवं उपयोगिता का मूल्यांकन करना।

4. शोध पद्धति

यह अध्ययन द्वितीयक आँकड़ों पर आधारित है। जानकारी निम्न स्रोतों से प्राप्त की गई है—

- भारत सरकार की रिपोर्टें
- शोध-पत्र एवं जर्नल लेख
- आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट
- RBI रिपोर्ट
- MSME मंत्रालय की रिपोर्ट
- IMF एवं विश्व बैंक की रिपोर्ट

अध्ययन वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक प्रकृति का है। आँकड़ों का तुलनात्मक विश्लेषण करके निष्कर्ष प्रस्तुत किए गए हैं।

5. MSMEs पर COVID-19 का प्रभाव

COVID-19 महामारी के दौरान MSMEs को अनेक आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ा—

(i) उत्पादन में गिरावट

लॉकडाउन के कारण उत्पादन गतिविधियाँ बंद हो गईं।

(ii) श्रमिक संकट

प्रवासी श्रमिकों के पलायन से उत्पादन क्षमता प्रभावित हुई।

(iii) नकदी संकट

छोटे उद्यमों के पास सीमित नकदी भंडार होने के कारण कार्यशील पूंजी संकट उत्पन्न हुआ।

(iv) मांग में कमी

उपभोक्ता मांग घटने से बिक्री प्रभावित हुई।

(v) आपूर्ति श्रृंखला बाधित

कच्चे माल एवं परिवहन में बाधाओं के कारण उत्पादन लागत बढ़ी।

एक अध्ययन के अनुसार लगभग 40% MSMEs गंभीर वित्तीय संकट में थे तथा औसत राजस्व हानि 45% तक दर्ज की गई।

6. MSMEs के लिए सरकारी सहायता योजनाएँ

(i) आपातकालीन ऋण गारंटी योजना (ECLGS)

यह योजना मई 2020 में प्रारंभ की गई थी। इसके अंतर्गत MSMEs को बिना अतिरिक्त गारंटी के ऋण उपलब्ध कराया गया। मुख्य विशेषताएँ:

- ₹3 लाख करोड़ तक ऋण सुविधा
- कम ब्याज दर
- सरकारी गारंटी
- कार्यशील पूंजी सहायता

इस योजना से MSMEs की तरलता स्थिति में सुधार हुआ।

(ii) अधीनस्थ ऋण योजना

तनावग्रस्त MSMEs को पुनर्जीवित करने हेतु ₹20,000 करोड़ की अधीनस्थ ऋण योजना लागू की गई।

इसका उद्देश्य:

- NPA MSMEs को राहत
- पूंजी संरचना में सुधार
- व्यवसाय पुनः प्रारंभ करने में सहायता

(iii) फंड ऑफ फंड्स योजना

MSMEs को इक्विटी सहायता प्रदान करने के लिए ₹50,000 करोड़ की योजना प्रारंभ की गई।

लाभ:

- पूंजी निवेश में वृद्धि
- सूचीबद्धता को प्रोत्साहन
- व्यवसाय विस्तार

(iv) मुद्रा योजना

सूक्ष्म उद्यमों को कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराने हेतु मुद्रा योजना को और अधिक सक्रिय किया गया।

(v) RBI की राहत नीतियाँ

भारतीय रिज़र्व बैंक ने—

- ऋण मोरेटोरियम
- तरलता सहायता
- ब्याज दरों में कमी
- ऋण पुनर्गठन

तालिका-1

COVID-19 के दौरान MSMEs हेतु प्रमुख सरकारी योजनाएँ

योजना	राशि (₹ करोड़)	उद्देश्य
ECLGS	3,00,000	कार्यशील पूंजी एवं ऋण सहायता
अधीनस्थ ऋण योजना	20,000	तनावग्रस्त MSMEs को राहत
फंड ऑफ फंड्स	50,000	इक्विटी सहायता
PMEGP	13,554	रोजगार एवं स्वरोजगार
मुद्रा योजना	परिवर्तनीय	सूक्ष्म उद्यम ऋण

स्रोत: MSME मंत्रालय एवं सरकारी रिपोर्टें।

7. सरकारी योजनाओं का आर्थिक विश्लेषण

(i) रोजगार संरक्षण

सरकारी योजनाओं ने MSMEs को बंद होने से बचाया तथा रोजगार संरक्षण में सहायता की। PMEGP योजना के माध्यम से लाखों रोजगार उत्पन्न हुए।

(ii) तरलता में सुधार

ECLGS योजना के कारण MSMEs को कार्यशील पूंजी उपलब्ध हुई। इससे उत्पादन गतिविधियों को पुनः प्रारंभ करने में सहायता मिली।

(iii) बैंकिंग क्षेत्र पर प्रभाव

सरकारी गारंटी के कारण बैंकों द्वारा MSMEs को ऋण देने में वृद्धि हुई।

(iv) डिजिटल परिवर्तन

महामारी के दौरान डिजिटल भुगतान एवं ई-कॉमर्स के उपयोग में वृद्धि हुई। कई MSMEs ने ऑनलाइन व्यापार मॉडल अपनाए।

(v) सीमाएँ एवं चुनौतियाँ

हालाँकि योजनाएँ उपयोगी थीं, फिर भी—

- कई MSMEs योजनाओं से अनभिज्ञ रहे।
- छोटे उद्यमों को बैंक ऋण आसानी से नहीं मिला।
- ऋण प्राप्ति प्रक्रिया जटिल थी।
- अनौपचारिक MSMEs को कम लाभ मिला।

Reedit आधारित चर्चाओं में भी MSME योजनाओं की जानकारी एवं प्रक्रियात्मक जटिलताओं को प्रमुख समस्या बताया गया।

तालिका-2

महामारी के दौरान MSMEs की प्रमुख आर्थिक समस्याएँ

समस्या	प्रभावित MSMEs (%)
राजस्व में गिरावट	45%
आपूर्ति श्रृंखला बाधा	50%
श्रमिक संकट	42%
नकदी संकट	60%
डिजिटल अवसंरचना की कमी	35%

स्रोत: विभिन्न शोध अध्ययनों पर आधारित संकलित आँकड़े।

8. डेटा विश्लेषण

उपलब्ध आँकड़ों से स्पष्ट होता है कि COVID-19 महामारी के दौरान MSMEs को गंभीर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। अधिकांश उद्यमों में बिक्री, उत्पादन एवं रोजगार में भारी गिरावट दर्ज की गई। ECLGS योजना के माध्यम से ऋण

उपलब्धता बढ़ी तथा कार्यशील पूंजी संकट में कमी आई। RBI की रिपोर्टों के अनुसार MSME ऋण वृद्धि महामारी के बाद धीरे-धीरे सुधरी।

हालाँकि, योजनाओं का लाभ मुख्यतः संगठित एवं बैंकिंग प्रणाली से जुड़े MSMEs को अधिक मिला। छोटे एवं अनौपचारिक उद्यम अपेक्षाकृत कम लाभान्वित हुए। आर्थिक विश्लेषण से यह भी स्पष्ट होता है कि डिजिटल तकनीक अपनाने वाले MSMEs अधिक तेजी से पुनर्बहाल हुए। डिजिटल भुगतान, ऑनलाइन विपणन एवं ई-कॉमर्स ने व्यवसाय संचालन में सहायता प्रदान की। इसके अतिरिक्त, भुगतान में देरी MSMEs के लिए एक बड़ी समस्या बनी रही। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार MSMEs के लगभग ₹8.1 लाख करोड़ भुगतान लंबित थे।

9. निष्कर्ष

COVID-19 महामारी ने MSME क्षेत्र को गंभीर आर्थिक संकट में डाल दिया, किंतु भारत सरकार एवं RBI द्वारा लागू सहायता योजनाओं ने इस क्षेत्र को स्थिर बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ECLGS, अधीनस्थ ऋण योजना, फंड ऑफ फंड्स तथा मुद्रा योजना जैसी नीतियों ने MSMEs को वित्तीय सहायता, कार्यशील पूंजी एवं रोजगार संरक्षण प्रदान किया।

अध्ययन से स्पष्ट होता है कि सरकारी योजनाओं के कारण MSMEs की आर्थिक पुनर्बहाली संभव हुई, किंतु योजनाओं की पहुँच, जागरूकता की कमी तथा प्रक्रियात्मक जटिलताओं जैसी समस्याएँ भी बनी रहीं। विशेष रूप से सूक्ष्म एवं अनौपचारिक उद्यमों को योजनाओं का सीमित लाभ मिला।

भविष्य में MSMEs के सतत विकास के लिए निम्न कदम आवश्यक हैं—

- सरल ऋण प्रक्रिया
- तकनीकी सहायता
- ग्रामीण एवं सूक्ष्म उद्यमों पर विशेष ध्यान
- डिजिटल प्रशिक्षण
- समय पर भुगतान व्यवस्था
- वित्तीय साक्षरता

अतः यह कहा जा सकता है कि COVID-19 महामारी के दौरान सरकारी सहायता योजनाएँ MSMEs के पुनरुद्धार में महत्वपूर्ण सिद्ध हुई, किंतु इनके प्रभाव को और अधिक व्यापक एवं समावेशी बनाने की आवश्यकता है।

संदर्भ सूची

1. [International Monetary Fund \(IMF\)](#)
2. [World Bank](#)
3. [Ministry of MSME, Government of India](#)
4. Akhilesh K. Sharma (2022), "Implications of Policy Initiatives for MSMEs amid Economic Disruptions Caused by COVID-19".
5. Silu Muduli (2022), "Impact of COVID-19 Packages on MSME Financing in India".
6. Subhash Sambhaji Agale (2021), "Economic Consequences of COVID-19 Lockdowns on Indian MSMEs".
7. Behera, Mishra et al. (2021), "COVID-19 Pandemic and MSMEs: Policy Response for Revival".
8. RBI Annual Report, 2021-22.
9. Economic Survey of India, 2025-26.
10. Press Information Bureau, Government of India.